



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

आधिकार सं प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1979/आश्विन 2, 1901

No. 191]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 1979/ASVINA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना संख्या 40-आईटी/सीपीएन/79

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1979

विषय :- जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1978-79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए नियम तथा शर्तें।

नियम संख्या आईटीसी/39/18/78.—1978-79 के लिए जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई जापानी अनुदान सहायता यैन 2.9 बिलियन (यैन 2,900,036,000) के अधीन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आयातों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शामिल होने वाली नियम तथा शर्तें जो कि परिशिष्ट 1 और 2 में अलग-अलग दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

सी० रैंकरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात नियंत्रण

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 49 आईटीसी पीएन/79 दिनांक 24-9-1979 के लिए परिशिष्ट-1

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन (यैन 2,900,036,000) के जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

650 GI/79—1

खण्ड I—सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता आईटीसी एक और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्रोत देशों से हुआ है तो संभरण ठेके का समझौता बार्ता करते समय आयातक को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश में आयात किए गए ऐसे घटकों का, आयात शुल्क सहित कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30% से कम है। ऐसे मामले में संभरणों से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न कर लेना चाहिए। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मर्चे आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1978-79 के लिए 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा"। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये लाइसेंस संकेत "एम/जे० एन० होगा"। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रण के आयात लाइसेंस के अपेक्षित पत्र में भी दुहराये जाएंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता

(939)

के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपये में भारत में चुकाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इन्हें लाइसेंस पर ही प्रसारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) उसके आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों की लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर किए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "उसके आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा किए गए उन क्रय आदेशों या क्रय सविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अभिकर्ताओं के आदेशों/और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

1 (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शंट का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टी सी एम अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1 (5) में गया उल्लिखित पक्ष के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सकें इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि हम लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (टी सी एम अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाद की न हो।

खण्ड-2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखे जाने वाली विशेष बातें :

2(1) (क) ठेके का मूल्य येन या यू० एम० डालर या पाँच स्टर्लिंग में एक ग्रेन एक सेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूप में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाँ पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रवर्गित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अभिव्यक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आप. इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

2(2) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू० एम० डालर या 8,00,000 पाँच मूल्य तक (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) के अलग-अलग आयतों के लिए लाइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। उसे अनुबन्ध-1 में सूची बद्ध देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पृष्ठता की आवश्यकता नहीं है।

2(3) लेकिन, जिस मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त 2(2) में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाते हैं (भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से किसी एक का चयन पूर्वक अनुमर्ण करना चाहिए :—

(क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2(4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी संदर्भ का अर्थ जैसा भी मामला हो, निविदा अथवा अधिप्राप्ति से होगा। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीददारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें :—

1. पात्र संभरकों की एक विशेष देश में या देशों की सीमित संख्या में विद्यमान हों।

2. पारस्परिक अखिल-बबल का या उपस्कार के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए या डिजाइन की विशेष आवश्यकताओं के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण, व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी आवश्यक हो।

3. खरीददारिया आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती हों इसलिए, लाइसेंसधारी को सलाह दी जाती है कि जिस मामले उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा।

2(5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारंटी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको श्रुतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हथोस्ताह हो जाएं।

(ग) बोली खूल जाने के बाद बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बाण्ड या गारंटियां रिहा कर देनी चाहिए।

2(6) आयात लाइसेंस के मद्दे केवल एक संविदा प्रविष्ट की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन से लेना चाहिए।

2(7) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्त्रोत देशों का राष्ट्रिक होना या पात्र स्त्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खण्ड-3

संभरण ठेका में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होंगी चाहिए :-

3(1) 1978-79 के लिए, 2.9 विनिमय के अनुदान सहायता से सम्बद्ध इस संधिदा की व्यवस्था 17 मार्च, 1979 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) संभरको को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1978-79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० आ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अर्पित हों।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हों और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और इसके लिए सम्बन्धित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास टोकियो को सूचना देगा और अर्पित पोत परिवहन लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक व्योरे देने हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

3(5) नीचे सकेतिक प्रपत्र (तीन प्रतियों में) में एक प्रमाण-पत्र :-

"मैं (हम) एतद्वारा यह स्पष्ट करता हूँ/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी [पात्र स्त्रोत देश] में पंजीकृत है और पात्र स्त्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है या पात्र स्त्रोत देशों में पंजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित है।"

3(6) यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या औपचारिक बुनिदा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए :-

(1) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विनिर्दिष्टकरण प्रकाशित किया गया था।

(2) उन पाठियों का नाम जिन्होंने निविदा पृष्ठताल के प्रति बाध-क्षीत की।

(3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप में निम्नतम उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण।

टिप्पणी :- पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति संधिदा का विस्तृत व्योरा अनुबन्ध-2 में देखें।

खण्ड 4- भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4(1) पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाईसेंस-धारी को दोनों पक्षों और विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या विदेशी संभरको को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए अथ आदेश और विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां,

जो सब प्रकार से पूर्ण हों, सम्बन्धित बैंक आयात लाईसेंस की दो फोटो प्रतियां सहित और अनुबन्ध-3 में सलग्न प्रपत्र "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन" उपर्युक्त क्रियाविधि संधिदा में आवश्यक प्राणीधनों से उत्पन्न सभी संधिदा संधिधनों के लिए भी लागू होंगी। एक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) के साथ साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हुए भेजने चाहिए।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज, "ए/पी" जारी करने के लिए आवेदन-पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टीसी एम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के राजदूतावास टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में संभरको को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र" (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और टी सी एम अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को प्लॉकित की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना में संभरको को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को देय बैंक अर्च भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड-5—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व :

5(1) मूल विनिमय पात परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक का भेजे जाएंगे या भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 के ण में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का मुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई या धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी संभरक का बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की नियति से वास्तविक रुपया जमा करने का नित्य तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष को दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत का दर से हिमाव लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं०-46 आई टी सी (पो एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखों में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 द्वारा आशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की ये धनराशि के बराबर रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य

नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं०-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम को मिश्रित दर होगा या वह दर होगा जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरो से दस्तावेज देने से पहले ही देय धनराशि लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रूपराजमा करना चाहिए वह 'कि डिपोजिट्स एण्ड एडवॉन्स 843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फोर परचेजिंग एटसेक्टो एन्ड परचेजिंग परसेस ग्रांट ऐंड फाम गवर्नमेंट जापान फॉर 1978-79 (येन 2.9 बिलियन ग्रांट ऐंड)

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, टीम हवारी दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को किसी शाखा या इसके उत्तमोत्तम शाखा या राष्ट्रीय बैंक (हुन्डोकर्ता) से प्राप्त एक हुन्डी (डिमान्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हवारी शाखा, दिल्ली-6 (हुन्डी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968 सं० 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132 आई० टी० सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेख में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसे मांग किए जाने के बाद मान बिना के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अनिवार्य धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। आखिर के विभिन्न कॉलमों को भरते समय आयातकों उनके बैंकरो को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के परा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और, प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ध्येय" में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना बालान में निम्नलिखित ध्येय निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है

(ङ) जमा की गई कुल धन राशि

(व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में समतुल्य रूपराजमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है।)

उसके पश्चात् सी एएए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संवर्धन देने हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को सन्तन

करने हुए खजाना बालान रूपराजमा करने का साध्य देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी एएए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रूपराजमा का निक्षेप बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी एएए वित्त मंत्रालय (प्राधिकार कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(5) भारत में सम्बद्ध बैंक ऑफ इण्डिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपराजमा निक्षेपों की धनराशि का पुष्टीकरण करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को भेजना चाहिए।

खण्ड 6 विविध शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोत लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोत लदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी एएए प्राधिकार कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यू सी ओ. बैंक बिल्डिंग संपद मार्ग नई दिल्ली को भजनी चाहिए।

6(2) संभरकों का विशेष शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी का चाहिए कि ये आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक का अवगत करावे जो सम्पत्ति का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठता तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबन्ध-1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें बैंक की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1978-79 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी प्राधारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों या अनुदेशों या आवेदनों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

6(6) अनुबन्धों की सूची

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात नियंत्रण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध—1 पात्र स्त्रीय देशों की सूची

अनुबन्ध—2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।

अनुबन्ध—4 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र।

अनुबन्ध—5 मान की प्राधिप्राप्ति की विस्तृत क्रियाविधि।

अनुसूच-1

(सर्वभूत खंड--1 कटिका 1(5))

पात्र स्त्रोत देशों की सूची

(क) श्री ई सी ई देश

आस्ट्रेलिया
आस्ट्रिया
बेल्जियम
कनाडा
डेनमार्क
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी मध्य गणराज्य
यूनान
आइसलैंड
इटली
जापान
आयरलैंड
लक्समबर्ग
नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नार्वे
स्वीडन
स्विट्जरलैंड
तुर्की
यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका उत्तरी सहारा
मिश्र
मॉरोको
तुनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
बरुंडी
केमरून
केप बर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतन्त्र,
चाद
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
जाम्बिया
कांगो, दमोह गणराज्य
इक्वेटोरियल गार्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कोनियो,
लेसोथो
लद्दबीरिया
मालगासी गणतन्त्र
मलावी
माली
मालिनेनिया

मारीशस
मोजाम्बिक
नाइगरा
पुर्तगाली गिनी
रियूनियन
रोडेशिया
रवान्दा
संट केनिना और डेम (2)
साओटोम और प्रिन्साइड
सेनेगाल
सेजिक्ज
सियरा लियोन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेने प्रोपर्स और इस्साम
टोगो
युगान्डा
तजानिया गणतन्त्र मघ
अपर वोल्टा
जाम्बे गणतन्त्र
जाम्बिया

3 अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बेहमस
बारबाडोस
बेनाइज
बर्गुडा
कोस्टोरिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतन्त्र
एल साल्वेडोर
गुवातेमाल
घाटेमाला
हेली
होन्डुरस
जमेका
मार्टिनिक
मेक्सिको
नीदरलैंड एन्टिलीज
निकारागुवा
पनामा

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डी पो द्वीप सहित

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित --

असेन्शन, ट्रिस्टन डाइन एक्ससिबिलिस, माइटिगेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरैबा, बोनाहुरे क्युराकाओ साहा,
सेन्ट मार्टिन
(दक्षिण भाग)
सेन्ट पियरी मिकेलोन
ट्रिनिदाड और टोबैगो
वेस्ट इन्डीज (शाखा) एन० आई० ई०

(क) सम्बन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित (2)

- 4 दक्षिणी अमरीका
अर्जेंटीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरू
सूरिनाम
उरुग्वे
- 5 मध्य पूर्वी एशिया
बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमान
सिरियाई अरब गणतन्त्र
यूनाइटेड अरब इमिरात
यमन अरब गणतन्त्र (3)
यमन जनवादी डी० आर (4)
- 6 दक्षिणी एशिया
अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालदीव
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका
- 7 सुदूर पूर्वी एशिया
बर्मा
हांगकांग
खमेर गणतन्त्र
कोरिया गणतन्त्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
ब्रियतनाम गणतन्त्र
ब्रियतनाम जनवादी गणतन्त्र
- 8 ओसिनिया
कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नौरू
न्यूकैलेडोनिया
- न्यूहेसिसेम (त्रि और फे)
हिपू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
मोलायन द्वीप समूह (त्रि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिमी समाओ
- 9 यूरोप
साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
टुर्की
यूगोस्लाविया
- (ख-2) ओ० पी० ई० मी० के सत्रस्य या सहायोगी देश
अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतन्त्र
गेबान
नाइजीरिया
हक्वोडोर
बेन्जुएला
ईरान
इराक
कुवैत
कासार
सऊदी अरब
आबु धाबी
हन्डोनेशिया
- (1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेन्ट क्रिस्टोफी) नेविस अगुइला, सेन्टलुशिया और सेन्ट विसेन्ट ।
(2) मुख्यद्वीप मोन्तेसरेन, सेमान, तुर्क और काइकोन और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।
(3) अजमान, डूबल, पुत्राईरद, राम अज सैनाह शारजाह और उम अल कवैलेन ।
(4) अदन और विभिन्न मुल्तनत और अमीरत सहित ।
(5) मोनायटो द्वीप (साहिती सहित) को शामिल करते हुए, ब्रास्ट्रल द्वीप समूह, दुआमोट, जाम्बियर ग्रुप और माकेसन द्वीप समूह ।
(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रवेश कागोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।
- अनुसन्ध—2
- प्राप्त पण्य सूची
- 1 रोलज
2 विशेष हस्तात और मिश्रधातु हस्तात सहित हस्तात
3 टूका और टूकटरो के विनिर्माण के लिए मशटक, मयाजक और पुजें
4 रसायन
5 भारत-आपान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुजें, मशटक और कच्चा माल

- 6 बिजली के हार्न के लिए सघटक, संयोजन और फालतु पुर्जे।
- 7 मशीनरी, सघटक, संयोजन, फालतु पुर्जे और कच्चा माल।
- 8 भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपकरण।
- 9 बम्बई हाई आफ शोर डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और उपकरण।
- 10 उर्वरक और ऐसी अन्य मर्चें जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र संख्या

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० प्रो०, बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—1978-79 के लिये 2.9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता
येन के अधीन जापान से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से
..... जो कि आयात के संबंध में है..
..... संबंध सभरक के नाम में बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के
लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये हम आपको
निम्नलिखित ध्येय प्रस्तुत करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या विनांक और मूल्य और वह तारीख
जिस तक वैध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये
कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव
के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) निविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली
भारतीय एजेंट के कमिशन की घनराशि
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) सभरकों के साथ की गई निविदा की संख्या और विनांक
- (ञ) सभरक का नाम और पता और पात्र प्रमाण पत्र भी भेजे
(दो प्रतियों में)।
- (ट) वे भुगतान गतों और संभावित निधि जिनको संविदा के अन्त-
र्गत भुगतान देय होंगे।
- (ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

- (ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय दिये जाने वाले
दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करे)
प्रत्येक सेटों की सं० और उनका निपटान दिखाने हुए।
- (ढ) पोनसदान अनुदेश (वाहतान्तरण / पार्द-ग्रिपमेट की अनुमति दी
गई है या नहीं निविष्ट कीजिये)।
- (त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाएँ) कर की
गई है। यदि हा तो ऐसी निविदा की दिनांक और मूल्य।

भवदीय

अनुबंध-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय :—2.9 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन
आयात—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों
के अनुसार आपको एतद्वारा यथा सक्षम ध्येय (जो परिशिष्ट में दर्शाए
गए हैं) के अनुसार सर्वश्री के नाम में
..... येन की घनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत
किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए०/पी०) की पावती
के बारे में ठेकेदार को सूचना दे और प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति
जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजकुतावास, टोकियो और इस
मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान
परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आप को यदि कोई हो तो दस्तावेज के लिए
दिया जाने वाले बैंकिंग भाड़ों महित भाड़े भी सीधे ही आयातक
के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी सभरकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज
के आधार पर आप के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी
सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी
चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि-
कार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7 यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध
रहेगा।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र संख्या
..... विनांक के सदर्थ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से वन्सार्बत प्राप्त करने पर विदेशी संभरको को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करे। संभरको को भुकाई गई धनराशि के बराबर रुपया की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या 8-आई० टी० सी० (पी० एन०) / 76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरको को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरको को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में मुख्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इसमें अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको जापानी संभरको को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट विए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6।

(आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुन्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 68 दिनांक 24-10-1968, संख्या-132 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 71 दिनांक 5-10-71 संख्या-74 आईटीसी/पीएन/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या-103 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर बिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह डिपोजिट्स एण्ड एंडवांसिज -843 मिलियन डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिस एटमेकटा एक्वाइपरचेजिस ग्रान्ट ऐंड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1978-79 (येन 2.9 बिलियन ऐंड)।

जिन मामलों में मुख्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या -132 आई० टी० सी० (पी० एन०) / 71 दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें जालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अवगणन पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी-

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में मुख्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की भुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की है उसके साथ जमा किए गए मुख्य रुपए का पूरा ब्योरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरको के बैंक के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंक खर्च और बैंक आफ इंडिया टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इण्डियन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी० सी० एम०) शाखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन।

1 प्रस्तावना

जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.9 बिलियन येन की अनुदान सहायता की रकम इस मार्ग दर्शन में निर्धारित अधिप्राप्ति की क्रियाओं के अनुसार उनकी आनुषांगिक पण्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए पात्र स्नात देशों के बीच कार्य कृशलता के लिए और बिना किसी भेदभाव के व्यापक उपयोग की जाएगी।

2 अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होगी :-

- (1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
- (2) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
- (3) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति
- (4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी अधिकरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी।

(ख) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है।

(ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में अधिप्राप्ति को स्वीकार करना सम्भव है।

- (1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन 1,500,000 य० एम० डालर या 800,000 पौड स्टालिंग से अधिक नहीं है।
- (2) जहां ग्रहण संभरको की संख्या सीमित है।
- (3) जहां अन्तर्बंदी या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए विशेष विशिष्टियां, ड्रेड नाम या पदनाम के संवर्ध में या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण पण्य वस्तु की खरीद करनी है।
- (4) जहां या तो क्रियाविधि अथवा क्रियाविधि (2) या उपर्युक्त (1), (2) और (3) से भिन्न किसी कारण से (उदाहरणार्थ आपात कालीन अधिप्राप्ति) क्रियाविधि के लिए लागू नहीं समझा जाएगा।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खंड के 1-3 में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता से सम्बन्धित कर्जदार की पुष्टि प्राप्त करेगा।

3. संविदा की शर्तें :-

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तयुक्त किए जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी।

1. पण्यवस्तुओं की शर्तें

चूंकि इस अनुदान सहायता का उपयोग पात्र स्त्रोन देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के लिए खर्चों का वित्तदान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विषयक मद पात्र स्त्रोन देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य-वस्तुएं होंगी और पात्र स्त्रोन देशों में भारतीय पत्तन को भेज दी जाएगी यदि पात्र स्त्रोन देशों से आयातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस

प्रतिगत (30 प्रतिशत) कम है तो सूचीबद्ध पण्यवस्तुएं विन्ययान की जाएगी भले ही वे संबिदा की मदों में सूचीबद्ध पण्यवस्तुओं के षण के रूप में गैर पात्र ज्ञात देशों में आयातित भाग के रूप में शामिल की गई ह। ऊपर उल्लिखित फार्मूला —

आयातित कीमत + आयात शुल्क

— × 100

संभरक की जहाज पर्यंत मिश्रित कीमत

2. संभरक की भर्तें

संभरक पात्र ज्ञात देशों का राष्ट्रिक ढांगा, या पात्र ज्ञात देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा ।

3. आयातक की भर्तें

सशस्त्र सेना या उससे सामान्यता प्राप्त भारतीय सस्त्राधों द्वारा किन्हीं भी पण्यवस्तुओं की अधिप्राप्ति श्रृंख के अन्तर्गत पात्र होगी ।

4. मुद्रा का मूल्य बर्ग

संबिदा क्रमशः एक सेन (बाई 1 00), एक सेन्ट (सी० 1 00) या एक पैनी (पी० 1 00) से कम किसी भिन्न के बिना ही आपानी सेन, यूनाइटेड स्टेट डालर या स्टलिंग पौण्ड में निर्धारित की जायेगी और देव होगी

5. संबिदा का मानक प्रपञ्च

(क) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तदान की जाने वाली खबिदा में निम्नलिखित सबे शामिल की जायेगी :—

- (1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
- (2) संबिदा की संख्या और दिनांक
- (3) पण्यवस्तुओं का नाम और मूल स्थान
- (4) संबिदा का मूल मूल्य और मात्रा
- (5) अदायगी की तारी
- (6) भुगतान और पोतलदान अनुसूची
- (7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संबिदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप से पुष्टि आदेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा दिये गये विक्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी स्वीकार्य हैं ।

(ग) पात्रता की निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संबिदा में शामिल किया जायेगा ।

“मैं (हम) एतद्वारा उल्लेख करता हूँ/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी (पात्र ज्ञात देश) में पंजीकृत है” ।

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान अनुदान गृहायता पर हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 1979 को या बाद में किया जायेगा । सिद्धांत के रूप में, संभरक की पोतलदान की पूरी अवधि संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय बैंक आफ इंडिया, टोकियो नकदी के रूप में अंश की जाएगी ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संबिदा का टेडर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा मागू की जावे तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जावेगी :—

650 GI/79—2.

(1) विज्ञापन देकर

ओपचारिक बूली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संबिदाओं में बोली मागने के लिये भारत से सामान्यतः रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जायेगी ।

(2) बोलियों के मागने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच के समय का अन्तराल ।

बोली तैयार करने के लिये अनुमित समय बहुत बड़ी सीमा तक संबिदा के महत्व और पेचोदगी के ऊपर निर्भर करेगा । सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिये कम से कम 30 दिनों स्वीकृत किये जाने चाहिये । किन्तु, अनुमित समय प्रत्येक संबिदा से संबंधित ह्रासतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये ।

(3) बोली बोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अंतिम पावती के लिये और बोली खाने की तिथि, समय और स्थान की बोली धामंत्रण में घोषित किया जाना चाहिये और सभी बोलियां निर्धारित समय पर बूले धाम खोली चाहियें । इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना बोले ही लौटा देना चाहिये । यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कूल घनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिये और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिये ।

(4) बोली बाद अथवा गारंटिया ।

बोली करने के मामले में, बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, किन्तु इतने ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिये जिससे उपयुक्त बोलीकार निश्चसाहित हो जाये ।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खूल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहियें ।

(5) मापवण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापवण्डों का उल्लेख किया जाता है, जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिये कि आपान औद्योगिक मापवण्ड या अन्य स्वीकार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय मापवण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुएं जो मापवण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापवण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जायेगा ।

(6) बाण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाये रखने के लिये मानकीकरण की एक द्विती की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिये और उन्हें एक केवल बाण्ड नाम, सूची सं० या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिये । बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिये जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उसमें है ।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमानत के रूप में कोई प्रपञ्च होना चाहिये । यह जमानत या दो बैंक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है ।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी स्पष्टता में फालतु खर्च होता हो, राजस्व को हानि हो या आयातक के लिये अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहियें ।

9. विवाह स्थितियाँ (फोर्स मैजूर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई सविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करने हुए हम सम्बन्ध में त्राक्याण जानें चाहिए कि सविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दाहिने को न पूरा करना उस हालत में एक चुक नहीं माना जायेगा यदि ऐसी चुक विवण स्थितियों (फोर्स मैजूर) के फलस्वरूप हुई है " सविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।

(10) झगड़ों का निपटारा

झगड़ों के निपटारे में संबंधित व्यवस्थाएं सविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहियें। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएँ अन्तराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाये गये "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों की स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहियें।

(11) मूल्यांकन

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचन संख्या 49 आईटीसी (पॉपुलर)/79, दिनांक 24-9-1979 का परिशिष्ट 2।

जापान सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के प्रायातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें

खण्ड 1—सामान्य शर्तें

1. (1) जापान सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2.9 बिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता सीईसीडी और विकासशील देशों के लिए बन्धनमुक्त है। तथानुसार, इस अनुदान सहायता के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएँ और उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक सेवाएँ जापान और अनुबन्ध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों में आयात की जा सकती है। ये देश इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। लेकिन, यदि लाइसेंस के अधीन आयात की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप से उत्पादन आयात स्रोत देश या देशों में हुआ है तो संभरण ठेके की समझौता वार्ता करते समय आयातक की इस बात का मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि संभरण ठेके के देश के आयात किए गए ऐसे घटकों का आयात मुक्त सहित कुल लागत बीमा, भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से 30 प्रतिशत से कम हैं। ऐसे मामले में संभरण ठेके में सहमत कर देना चाहिए। इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत आयात की जाने वाली पात्र पण्य वस्तुओं की सूची अनुबन्ध 2 में दी गई है।

1. (2) लाइसेंस पर एक शीर्षक 1978-79 के लिए 2.9 बिलियन येन जापानी अनुदान सहायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/एन" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रप्रेषण पत्र में भी दूहराए जाएंगे।

1. (3) वे बैंक खर्च जिनका परेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकर्ता को अनिवार्य रूप से भारत में भुक्ताना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए, लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1. (4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जायेगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी की सम्बद्धता लाइसेंस प्राधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में अधिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1. (5) पक्के आदेश अनुबन्ध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरणों को लागत बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत

और भाड़ा के आधार पर किए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर अधिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग) तार्थ स्थाक, नई दिल्ली को भेजे दिए जाने चाहिए। 'पक्के आदेश' का अर्थ विदेशी संभरणों को भारतीय लाइसेंस धारी द्वारा किए गए उन त्रय आदेशों या त्रय सविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरण द्वारा विधिवत् समर्थित हो या भारतीय आयातक और विदेशी संभरण द्वारा विधिवत् समर्थित हो। विदेशी संभरणों के भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकृतीय नहीं है।

1. (6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेके की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जबकि कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग, (टीसीएम अनुभाग) को नहीं पहुँच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीने के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस की सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जानी है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, अधिक कार्य विभाग (टीसीएम अनुभाग), तार्थ स्थाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंसधारी को परेषित करेंगे।

पोलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30-6-1981 के बाद की न हो।

खण्ड 2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष शर्तें

2. (क) ठेके का मूल्य येन या यू.एस. डालर या पीड स्टलिंग गैंगक येन, एक सेन्ट या एक पैनी में कम की मात्र के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए, और हममें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में भुक्ताना चाहिए भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा अनुराग अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निहित किये गये भाड़े का खर्चा वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय अनुराग होगी।

(ख) सविदा में नकद भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात् जापानी संभरणों द्वारा बैंक आफ इन्डिया, टोकियो के पोलदान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर।

(ग) जब आदेश और संभरण द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अर्धजी प्रस्तुत में होने चाहिए।

2. (2) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00,000 यू.एस. डालर या 8,00,000 पीड मूल्य तक (भारतीय अधिकर्ता के कमीशन को छोड़ कर) के अलग-अलग प्रायातों के लिए लाइसेंसधारी संभरणों से सीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतंत्र है उसे अनुबन्ध 1 में सूचीबद्ध देशों से अन्तराष्ट्रीय निर्यात की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

2 (3) लेकिन, जिस मामले में सम्मरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त-2(2) में निर्धारित सीमा में अधिक हो जाते हैं (भारतीय अधिकारी के कमीशन को छोड़कर) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से किसी एक का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए।

- (क) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।
- (ख) औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना।
- (ग) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति।

2. (4) पात्र स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रेषण अन्तर्राष्ट्रीय अधिप्राप्ति के किसी भी स्तर पर का अर्थ जैसा भी मामला हो, निविदा प्रेषण अधिप्राप्ति से होगा। औपचारिक प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या प्रत्यक्ष खरीददार खरीददारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि में उन मामलों में छूट दी जा सकती है जिनमें —

- (1) पात्र सम्भरकों की एक सूची एक विशेष देश में या देशों की सीमा में मध्य में विद्यमान हो।
- (2) पारस्परिक अद्वन्द्वता का या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चय करने के लिए या शिक्षा के विशेष आश्वासन के कारण एक विशेष विशिष्टकरण, व्यापार नाम या पदनाम के मन्दर्भ में पण्य वस्तु की खरीददारी आवश्यक हो।
- (3) खरीददारों द्वारा आपातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में आती है इसलिये, लाइसेंसधारी को मलाह दी जाती है कि जिस मामले में उपर्युक्त पैरा 2(3) के (क) और (ख) की क्रियाविधि का सहारा नहीं लिया जा सकता है उसमें आर्थिक कार्य विभाग को मंदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर पात्रता के आधार पर विचार करेगा।

2 (5) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए: —

- (क) बोली लगाने के लिए निमन्त्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाली कम से कम एक प्रकाश में विज्ञापित करने पड़ेगा।
- (ख) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारण्टी सामान्य आवश्यकता है परन्तु उनको इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले, हतोत्साह हो जाए।
- (ग) बोली खुल जान के बाद बोलीकार का यथासंभव बोली बाण्ड या गारण्टी रद्द कर देनी चाहिए।

2 (6) आयात लाइसेंस के सम्पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक ही मरिबाद की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक मरिबाद करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से उचित बाद बिना मन्त्रालय आर्थिक कार्य विभाग में अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2 (7) सम्भरकों की पात्रता

सम्भरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा उसके रूप से नियमित व्यापिक व्यक्ति होगा।

भाग 3—सम्भरण ठेकों में निम्नलिखित बातें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए

3(1) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और 1978-79 के लिए 24 बरतियन में आपात अनुदान सहायता अध्यादेश 17 भाग 1979 के द्वारा समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी।

3(2) सम्भरकों की भुगतान "भुगतान के लिए प्राधिकरण" की माध्यम से होगा जो कि 1978-79 के लिए आपात अनुदान सहायता के अन्तर्गत बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो के नाम से सहायता लेता एवं लेखाकार नियंत्रक, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू.के. बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी सम्भरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार और दूसरी और आपात सरकार द्वारा अपेक्षित होगी।

3(4) जिस मामले में सम्भरक जापान में स्थित हो और वे भारत के दूतावास टोकियो से परामर्श करके पातलवान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो और यह कि इस उद्देश्य के लिए वे भारत के दूतावास टोकियो की माल की सुपुर्दी के विषय में सूचित करेंगे और इस प्रकार अपेक्षित पोतलवान से कम से कम चार सप्ताह पहले भारत के दूतावास को यह सूचना देंगे ताकि उचित व्यवस्था की जा सके। अपवादस्वरूप मामलों में जहाँ आयातक को आवश्यकता हो तो टोकियो की यह अवधि घटाई जा सकती है। आपात सम्भरकों को आवश्यक योग्य होने हुए प्रत्येक पोतलवान के बाद आयातक का एक केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रतिनिधि भारत के दूतावास टोकियो को भेजनी चाहिए।

3 (5) नीचे मरिबत प्रश्न में एक प्रमाणपत्र —

“मैं (हम) एतद्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियमित है अथवा पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट किए गए व्यापिक व्यक्तियों द्वारा नियमित है।”

खण्ड 4—आयात की अधिप्राप्ति के लिए और सम्भरण ठेके को पूर्ण रखने के लिए बिस्तृत क्रियाविधि अनुसूच 5 में निविदा की गई है

खण्ड-5—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

5 (1) पत्र आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर साइस प्रांगे का शाना पक्षा द्वारा विधिवत् हस्तक्षरित ठेके की चार प्रतियाँ या बिदेश सरकार की भारतीय आयातक द्वारा दिए गए पत्र आदेश और विदेशी सम्भरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियाँ, अनुसूच 3 में सार्वजनिक प्रश्न में एक आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) के साथ भी स्टाम्प समवर्तता द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम खण्ड 31 के अन्तर्गत विधिवत् निर्माण अनुसूच 6 में यथा निर्धारित प्रश्न में एक बैंक गारण्टी के साथ, भयर मचिव (टीसीएम अनुभाग) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली की साजपत्र खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने हुए भेजने चाहिए।

यदि किसी मामले में ठेका औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने या औपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र दा प्रतियाँ में भेजना चाहिए:—

- (1) उस अधिप्राप्ति का नाम जिसमें बोली का विशिष्टकरण प्रकाशित किया गया था।
- (2) उन पार्टियों का नाम जिन्होंने निविदा पृष्ठताछ के प्रति बातचीत की।

(3) यह निदिष्ट करत हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम उपर्युक्त बोली है, एक विशेष बोली (प्रस्ताव) चुनने का कारण।

5(2) बैंक गारण्टी—यह अन्तर्राष्ट्रीय जिसके लिए यह निम्नलिखित की जानी चाहिए।

बैंक गारन्टी में धनराशि के तृप्त्य रूप में प्रदर्शित करते हुए उस धनराशि के लिए होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकरण-पत्र मांगा गया है और इसमें अनुबन्ध-6 में यथा उल्लिखित व्याज तथा अन्य खर्च भी शामिल होने चाहिए। परिवर्तन की दर राजस्व तथा बैंक विभाग द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय की दर पर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित की गई सार्वजनिक सूचना सख्या-7 आई टी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस के जारी होने की तिथि की प्रचलित मुद्रा विनिमय की दर पर होगी। यह दर केवल लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारन्टी की मूल्य की गणना करने के उद्देश्य के लिए है। आयातों की लागत के लिए सरकारी लेखों में रुपया जमा करने के उद्देश्य के लिए तुल्य रुपये की गणना नीचे खण्ड-7 में निर्दिष्ट तरीके से करनी होगी।

5(3) यदि ठेके के वस्तावेज भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदनपत्र बैंक गारन्टी और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो बिना मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टीसीएम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और दस्तावेजों का एक सेट नियंत्रक सहायता लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मन्त्रालय, यू.सी.ओ. बिल्डिंग, पहली मजिल, मसद मार्ग नई दिल्ली और भारतीय दूतावास, टोकियो का भेजेगा।

खण्ड-6—समुच्चयार सभरको को भुगतान-भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र

6 (1) उपर्युक्त खण्ड-5(3) में उल्लिखित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षक नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय, यू.सी.ओ. बैंक बिल्डिंग, पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 जापानी सभरको को भुगतान करने के लिए अनुबन्ध-3 में दिए गए प्रपत्र में बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतिया भारतीय दूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक का बैंक और टीसीएम अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय को पृष्ठांकित करेगा।

6(2) भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (ए/पी) प्राप्त होने पर बैंक आफ इण्डिया, टोकियो इस पावती की सूचना जापान सरकार, भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक का बैंक और मीणस और ए की सूचना देते हुए सभरको को भी सूचना देगा। और भारतीय दूतावास, टोकियो को भुगतान का प्रबन्ध करेगा।

6(3) माल का पोत खदान करने के बाद विदेशी सभरको अपने बैंक का माध्यम से प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इण्डिया टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी सभरको को ठमक बैंक का माध्यम से रिहा करेगी।

6(4) प्राधिकरण पत्र में परामर्श के लिए और सभरको का भुगतान की व्यवस्था के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को बुलाए जाने वाले बैंक खर्च भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना ही बुलाए जाएंगे।

खण्ड-7—रुपया जमा करने का उत्तरदायित्व

7(1) मूल विनिमय पोन परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा होगी अथवा अनुबन्ध-3 में (धो) उल्लिखित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी। उस बैंक की दस्तावेजों के वे विनिमय सेट केवल इस बात की सुनिश्चय कर देने के बाद ही लाइसेंसधारी को देने चाहिए कि जापानी सभरको

बुकाई गई धन धनराशि के बराबर रुपया और उस धनराशि पर विदेशी सभरको को बैंक आफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगा कर व्याज सार्वजनिक सूचना सख्या-46 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी तबों में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिना, अर्थात् जिस दिन विदेशी सभरको भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया जमा किया जाता है के लिए देय है। दक्षिण सार्वजनिक सूचना सख्या-103 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा निर्धारित सार्वजनिक सख्या-74 आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतान की धन/यू.एस. डालर/पोड स्टॉकिंग धनराशि के बराबर रुपय की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सख्या-8 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिषद् की माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा, अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का सम्बद्ध भारतीय बैंक का उत्तरदायित्व होगा कि आयात वस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही वे धनराशि सरकारी लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने बैंकरो से वस्तावेज लेने से पहले ही वे धनराशि लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपयुक्त रुपया जमा करना चाहिए, वह "के डिपोजिट्स एण्ड एक्वालिज 843 सिविल डिपोजिट्स—टिपीजिट्स फॉर परफेजिंग एक्सचेंज एक्वालिज परफेजिंग ग्रान्ट एण्ड फ्रॉम यवनेमेंट आफ जापान फॉर 1978-79 (यन 2 9 बिलियन ग्रान्ट एंड) होगा।

7(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली, में सरकार की सख्त में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसर्ग किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुन्डीकर्ता) से प्राप्त एक एण्ड (डिमाण्ड ड्राफ्ट) का माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया तीस हजारी शाखा दिल्ली-6 (हुन्डी ग्राहक और प्राप्तक) का सार्वजनिक सूचना सख्या 184 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-1968, सख्या 233 आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-1968, सख्या-132 आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सख्या 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-1974 और सख्या-103 आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

7(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह धनराशि धनराशि सेवा खर्चों के नियमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। ज्ञातान के बिना कालसा का भारत समय आयातकों/उनके बैंकरो को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सख्या-103 आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 13-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सख्या 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-1971 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना-74 आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालसा धन परेषण और प्राधिकारों (यदि कोई हो) के पूर्व धनराशि में निरपत्राव रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। ज्ञातान ज्ञातान में निम्नलिखित जारी के निष्कर्षाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए —

(क) वित्त मन्त्रालय के प्राधिकार पत्र (भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र) संख्या और दिनांक

(ख) येन सभा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिचालन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी सभ्यता का भुगतान करने की तिथि

(घ) बकाए गए व्याज की धनराशि और वह अर्द्ध जिसके लिए यह गिना गया है।

(ङ) जमा की गई गई कुल धनराशि

(जागानी सभ्यता को भुगतान की तिथि में व्याज की गणना की जानी है और इसमें सरकारी लेखों में रक्कत जमा करने की नगरी भी शामिल है।)

उसके पश्चात् सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का सर्वेक्षण देने हुए और बीजक तथा पोट परिवहन वस्तु-बैज को सलमन करत खजाना खलान रक्कत जमा करने का माध्य देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए०ए० का भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रपट का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो से आयापनी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोट लवान वस्तुवैजो की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरापवाद रूप में किया जाना चाहिए और यह कि उसके तत्काल बाद सी०ए०ए०ए० वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

7(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रक्कत निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित एम प्रपक्ष भारतीय रिजर्व बैंक आफ इन्डिया को भेजना चाहिए।

7(5) बैंक गारन्टी और जिस सत्रानय सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र के अनुसार आभारों को पूर्ण करने के बाद भारतीय सम्बद्ध बैंक, बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सी०ए०ए०ए० से आवेदन कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए आवेदनपत्र अनुबन्ध-7 में दिए गए प्रपक्ष में दिया जाना चाहिए।

खंड—8 विविध शर्तें

8 (1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट

सम्प्रति खोले जाने के बाद आयातक को पोट लवानों और उसके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोटलवान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए०ए० का भेजना चाहिए।

8 (2) सभ्यता की विदेश शर्तें अधिसूचित करना

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों में सभ्यता की अधिसूचित करावे जो समझौते का पालन करने में सभ्यता पर प्रभाव डाल सकती हैं।

8 (3) विवाद

यदि समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सभ्यता के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उपरदायित्व नहीं लगी। बैंक आफ इण्डिया टोकियो द्वारा भुगतान में पूर्ण सभ्यता द्वारा पूरी की जाना बाला जहाँ भुगतान की जगहों के अधीन अनुबन्ध-1 में आयातक द्वारा साफ-साफ बना देनी चाहिए। विवादों में निपटन की जगहों के जगहों में शामिल होने चाहिए।

8 (4) न विदेश अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या जगहों मामलों से सम्बन्धित या आपान में 1978-79 के लिए अनुदान महावता के अधीन सभी आधारों का पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंस-धारी को पुरस्त पालन करना होगा।

8 (5) प्रतिस्पर्धा या उत्पन्न

उपयुक्त खण्डों में स्थित की गई जगहों के प्रतिस्पर्धा या उत्पन्न करने पर आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित नार्मार्ड की जाएगी।

8 (6) अनुबन्धों की सूची:

अनुबन्ध-1 पात्र आत देशों की सूची

अनुबन्ध-2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध-3 भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए आवेदन

अनुबन्ध-4 भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र का प्रारूप

अनुबन्ध-5 अधिप्राप्ति के लिए विस्तृत विवरण

अनुबन्ध-6 गारन्टी बाण्ड

अनुबन्ध-7 बैंक गारन्टी रिहा करने के लिए आवेदनपत्र का प्रारूप

अनुबन्ध --- 1

(सर्वतः खंड—1 कविका—1 (5))

पात्र आत देशों की सूची

क-यो०ई०सी०डी० देश

आल्बेनिया

आल्बिया

बेल्जियम

कनाडा

डेनमार्क

फिनलैंड

फ्रांस

जर्मनी सर्बीय गणराज्य

यूनान

आइसलैंड

आयरलैंड

इटली

जापान

लक्समबर्ग

नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नार्वे

स्वीडन

स्विटजरलैंड

तुर्की

यनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य

(ख) विकासशील देश और सीमांत

(ख-1) नान-आ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र

भारत

ट्यूनीशिया

2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्स्वाना

अरुंडी

केमरोन
 कैप नर्वी द्वीप समूह
 केन्द्रीय अफ्रीका गणराज्य (1)
 काव
 कमोरो द्वीप समूह
 कांगो दाहोमे गणराज्य (1)
 भूमध्यवर्ती गिनी
 इथोपिया
 जाम्बिया
 जाम्ना
 गिनी
 ग्राइवरी कोस्ट
 कीनिया
 लेसीथे
 लाइबेरिया
 गालागासी गणतन्त्र
 मलावी
 माली
 मारितेनिया
 मारिसस
 मोजम्बीक
 नाइजर
 पुर्तगाली गिनी
 रियूनियन
 रोडेसिया
 रवाण्डा
 सेंट हेलेना और जेप (2)
 साओटोम और प्रिन्सिप
 सेनेगल
 सेनेगल
 सियरालियोन
 सोमालिया
 सूडान
 स्वाजीलैंड
 टैरा फाफर्स और इस्वाथो
 टोगो
 तूवाल्वा
 संजानिया गणतन्त्र संघ
 अपर वोल्टा
 वाइरे गणतन्त्र
 जाम्बिया

3. अफ्रीका, उत्तरी और केन्द्रीय
 बेहमस
 बारबाडोस
 बेसाइज
 बरमुडा
 कोस्टारिका
 क्यूबा
 डोमिनिकन गणतन्त्र

एल साल्वेडोर
 गुवातेमाला
 हाती
 होन्डुरस
 जमैका
 मार्टिनिक
 मेक्सिको
 नीदरलैण्ड्स एन्टिपीज
 निकारागुवा
 पनामा
 सेंट पियरी और मिकेलोन
 ट्रिनिडाद और टोबागो
 बैस्ट इन्डो (शाखा) एन० धार्० ई०
 (क) सम्बन्धित राज्य (1)
 (ख) धातित राज्य (2)

4. दक्षिणी अफ्रीका

अर्जेंटीना
 बोलिविया
 ब्राजील
 चिली
 कोलम्बिया
 पस्कलेट द्वीप समूह
 फ्रांसिसी गिनी
 गुयाना
 पाराग्वे
 पीरू
 सूरीनाम
 उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बेहरीम
 इजराइल
 जोर्डन
 लेबनान
 ओमान
 मिरियाई अरब गणतन्त्र
 यूनाइटेड अरब एमिरात (3)
 यमन अरब गणतन्त्र
 यमन जनवादी डी० धार० (4)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
 बांग्ला देश
 भूटान
 बर्मा
 मालदिव
 नेपाल
 पाकिस्तान
 श्रीलंका

- (1) पहले स्वैभी गिनी का प्रदेश, फारनेन्डो पो० द्वीप सहित
- (2) निम्नलिखित द्वीपों सहित असेणसन, ट्रिस्टन डा हन एक्सेसिबिलिस्, नाइ-टिन्सोस गल्फ
- (3) मुख्य द्वीप समूह, अल्गा, बोर्नाइरे, क्युराकाओ, वाहा, सेंट, इस्टेसिट, सेंट, कार्टिन (दक्षिणी भाग)

- (1) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, वेनेड, सेंटक्रिस्टोफ (सेन्टक्रिस्टोफी) मेविल शंगूइला, सेंटलुसिया और सेंट विलेज
- (2) मुख्य द्वीप मोस्तेरन, मेमान, तुर्क और काइकम और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह
- (3) अजमान, कबान, फुजाइराह, राम भल बीमाह शाबवाह और उमाल कबेबेन
- (4) अरब और विभिन्न सम्पन्न और अमीरान सहित

7. मृदुर पूर्वी अशिया

बल्टी
हांगकांग
खमेर गणतन्त्र
कोरिया गणतन्त्र
लाओस
मलाया
मरोशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतन्त्र
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र

8. ओशनिया

लोकदीप समूह
किरी
गिल्बर्ट और राल्फ द्वीप
फ्रांसीसी पालिनीशिया (5)
नौरु
न्यूकालेडोनिया
न्यू हेब्रिडिस (फ्रि आ के)
हिड्यू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुवा न्यू गिनी
मोलोमान द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फुतुना
पश्चिमी मसीओ

9. यूरूप

साइप्रस
पिट्तेल्टर
श्रीक
माल्टा एम
स्पेड
टर्की
यूगोस्लाविया

(ख) 2) आ० पी०ई०पी० के सदस्य या संबन्धित देश

अल्बानिया
बोस्निया
बिश्नियान अरब गणराज्य
गार्बोस
नाईजीरिया
एक्वडोर
बेन्गुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कुवैतान
सऊदी अरब
आबू धाबी
इम्बोनेशिया

- (5) सोमायटी द्वीप समूह (नामिकी सहित) को शामिल करते हुए फ्रांसुज द्वीप समूह दुअरमोट, जाम्बियार द्वीप और मॉर्सेस द्वीप समूह।
(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीपसमूह और मेरिना द्वीपसमूह (गाम को छोड़कर)

अनुसूच 2

नाम परब सूची

1. राज्य
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात
3. टूफो और ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए संबद्धक, संयोजन और पुर्जे।
4. रसायन
5. भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फायरू पुर्जे, मशटक और कच्चा माद्य
6. बिजली के हृषों के लिए मशटक, संयोजन और फालतू पुर्जे।
7. मशीनरी मशटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माद्य।
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग नियम के लिए मशीनरी और उपकरण।
9. बम्पाई हाई आफ शोर डिप्लेमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और उपकरण।
10. उद्योग और ऐसी अन्य भव्य भव्य जिन पर आपस से सहमति हो।

अनुसूच 3

भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए प्राचीन-पत्र सेवा में,

सहायता सेवा एवं सेवा परीक्षा नियन्त्रक,
वित्त मंत्रालय,
प्राधिकार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय — 1978-79 के लिए 2 9 बिलियन की जापानी भुगतान सहायता के अन्तर्गत जापान से आयात।

ऊपर उल्लिखित भुगतान सहायता के अन्तर्गत जापान से आयात के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित व्यौरे भेजते हैं जिससे कि आप सम्बन्ध संस्करण के पक्ष में बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्राधिकार पत्र जारी कर सकें —

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाहमेस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तादीय जिम तक बंध है।
- (ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुली अन्तराष्ट्रीय निविदा पर आधारित हैं। इसके मामले में यदि कोई हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या मक्का का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उद्गम देश।
- (च) सविदा का कुल लागत और भाडा मूल्य (येन में)
- (छ) भारतीय रुपए में भुगतान के योग्य भारतीय एजेंट के कमीशन का अनुमानित (येन में) यदि कोई हो।
- (ज) कुल लागत और भाडा मूल्य (येन में) जिनके लिए प्राधिकारपत्र की आवश्यकता है।
- (झ) सभरको के साथ सविदा का नाम और दिनांक।

- (अ) संभरक का नाम और पता और पाबना पत्राण-पत्र (री प्रावर्षी मे) सत्यन किया जाए।
- (ब) भुगतान शर्तों और सम्भावित निषिद्धा जिनके संबंध में अनुसूचित भुगतान करना है।
- (ग) सुपुर्वशी को पूर्ण करने की सम्भावित निषिद्धा।
- (घ) बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो की भुगतान के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका नियंत्रण दर्शाते हुए)।
- (ङ) पोतलदान अनुदेश (क्या पोतलदान/आधिक पोतलदान अनुदेश है प्रवर्षा नहीं, दर्शाएँ)
- (च) भारत में आयातक बैंक का नाम और पता।
- (ज) किस अवधि तक वेध है यह दर्शाते हुए बैंक गारंटी की संख्या, दिनांक एवं मूल्य।
- (झ) क्या उसी लाइसेंस के अनुसूचित मजिदार् की गई है और यदि हाँ तो ऐसे मजिदार् की सं०, दिनांक और मूल्य।

भारतीय

अनुसूचक-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली

दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया
टोकियो शाखा
टोकियो (जापान)

विषय — 29 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात-भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 1.3.74 का लिए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपके एन्डोर्सर यथा सत्यन और (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार संबंधी के नाम से येन ... की धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/वी) की पाबनी के बारे में ठेकेदार का सूचना दे और प्रत्येक सूचना-पत्र की एक प्रति आपसे सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजस्व-भाग टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान [परिशिष्ट में यथा संज्ञित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आप को यदि कोई हो ना दस्तावेज के लिए प्रेषित किए जाने वाले बैंकिंग भागी सहित भाड़े भी सीधे ही आयातक के बैंक द्वारा निष्पत्ति किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरको द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेजों में आधार पर आप के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में सहायक और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र के लिए कोई भी सहायन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र ... तक बंध रहेगा।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक

को उनके पत्र संख्या

दिनांक

के संबंध में

2. आयातक का बैंक

उत्तम निवेदन किया

जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो बैंक से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरको को येन के बराबर कृपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरको को चुकाई गई धनराशि के बराबर ए/वी की गणना मार्ब-जनिक सूचना संख्या-8 आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 17-1-76 का अन्य ऐसी मार्ब-जनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार आपानी संभरको को भुगतान करने की तिथि को यथा परवर्षित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। संभरको को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखों में मुख्य कृपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए मार्ब-जनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर में व्याज भी सरकारी लेखों में जमा करना होगा। व्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको जापानी संभरको को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखों में कृपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर से यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल नेट दिए जाने में पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी धनुषी निकाशों या किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त का गई स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली-6

(आदेशित और आदाना) के नाम में और उसको येन दर्शनी हुई की के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान मार्ब-जनिक सूचना सं० 23.3-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, संख्या 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "डिपोजिट्स एण्ड एडवाइज-843 मित्रिय डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फॉर परफेजिस एडमिस्ट्रा एंडा परफेजिस ग्रान्ड गेट फाम दि एवर्नेमेंट ऑफ जापान फॉर 1978-79 (येन 29 बिलियन ग्रान्ट एंड)"

जिस मामले में मुख्य कृपया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी में मार्ब-जनिक सूचना संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नबद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिनिधि बैंक ऑफ इण्डिया टोकियो जापान से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्णबिबरण देने हुए धरोषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित को पर भेजी जाएगी —

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू.सी.आर्बैंक बिल्डिंग,
समद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य स्वरूप ऊपर संकेतित मार्बेजिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी टुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में व्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए व्याज का गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य स्वरूप का पूरा व्योम इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंक खर्चों और बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इण्डियन बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सोधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4 भारतीय भूतवास टोकियो।

5. अवर सचिव (टी सी एम) शाखा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत पण्य वस्तुओं की
अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन

1. प्रस्तावना

जापान की सरकार द्वारा बकाई गई 2.9 बिलियन येन की अनुदान सहायता रकमों का उपयोग इस मार्गदर्शन में दी गई अधिप्राप्ति की क्रिया-विधियों के अनुसार पात्र स्रोत देशों के बीच क्षमता और किसी भेद-भाव के बिना पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति और उनके लिए अनुषंगिक सेवाओं के लिए उचित विचार के साथ किया जाएगा।

2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होंगी :—

- (1) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना
- (2) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना
- (3) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति
- (4) सीधी खरीद

(क) सरकार और/या सरकारी एजेंसी द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी।

(ख) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी क्रियाविधि लागू हो सकती है।

(ग) लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम से अधिप्राप्ति कर स्वीकार करना सम्भव है :

- (1) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुसार जहां प्रस्तावित संविदा की धनराशि 300,000,000 येन, 1,500,000 यू.एस.डॉलर या 800,000 पौण्ड स्टर्लिंग से अधिक नहीं है।

- (2) जहां श्रद्धा संभरकों की संख्या सीमित है।

- (3) जिस मामले में किसी विशेष विशिष्टकरण, ट्रेड नाम या पदनाम के सदर्थ द्वारा किसी पण्य वस्तु की खरीद उपकरण के अन्तर-परिवर्तन या मानकीकरण, या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक हो।

- (4) जिस मामले में उपर्युक्त मामला (1), (2) और (3) (अर्थात् आपाती अधिप्राप्ति के मामले में) से भिन्न कारण द्वारा या तो क्रियाविधि (1) या क्रियाविधि (2) लागू हो।

(घ) ऊपर उल्लिखित किसी भी मामले में आयातक इस खण्ड के 1-3 तक में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता से सम्बद्ध कर्तदार को पुष्टि प्राप्त करेगा।

3. संविदा की शर्तें

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत विनाश बात को जाने वाली कोई भी संविदा निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी :

(1) पण्य वस्तुओं की शर्तें

चूंकि, स अनुदान सहायता का उपयोग पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं के लिए खर्चों का वित्त बान करने के लिए सीमित है इसलिए संविदा विशेषक मद पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं होंगी और पात्र स्रोत देशों से भारतीय पत्तन को भेज दी जाएंगी। यदि पात्र स्रोत देशों में आयातित भाग निम्नलिखित फार्मुले से तीस प्रतिशत (30%) से कम होगा तो सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं वित्तदान की जाएंगी मने हो वे संविदा की मदों में सूचीबद्ध पण्य वस्तुओं के अग्र के रूप में गैर-पात्र स्रोत देशों से आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हों। ऊपर उल्लिखित फार्मुला :—

$$\frac{\text{आयातित कीमत} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत}} \times 100$$

(2) संभरक की शर्तें

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा, या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा।

(3) आयातक की शर्तें

नगसन्न सेन; य, उमसे मान्यता प्राप्त भारतीय सम्पादकों द्वारा किन्हीं भी पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति इस ऋण के अन्तर्गत पात्र नहीं होगी।

(4) मुद्रा का मूल्य वर्ग

संविदा ऋण एक येन (बाई 1.50) एक सेन्ट (सी 1.00) या एक पैनी (डो 1.00) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी येन, यूनाइटेड स्टेट डॉलर या स्टर्लिंग पौण्ड में निर्धारित की जाएगी और येन होगी।

(5) संविदा का मानक प्रपत्र

(क) इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत वित्तदान को जाने वाली संविदा में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएंगी :

- (1) संभरक और आयातक का नाम और राष्ट्रिकता
- (2) संविदा की संख्या और दिनांक
- (3) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान
- (4) संविदा का मूल्य और मात्रा
- (5) अदायगी की शर्तें
- (6) भुगतान और पोनवशन अनुसूची
- (7) अन्य सामान्य विनियमन

(ख) दोनों पार्टियों द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित संविदा या विशेषी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आवेश द्वारा सममित विदेशी संभरक को भारतीय आयातक द्वारा किए गए विक्रय आदेश, या उनकी फोटो प्रतियां भी स्वीकार्य हैं।

(ग) पात्रता का निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविदा में शामिल किया जाएगा :

“मैं (हम) एतद्वारा उल्लेख करता हूँ/करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी (पक्ष स्रोत देण) में पंजीकृत है।”

(6) भुगतान

प्रत्येक भुगतान अनुदान सहायता की हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात् 17 मार्च, 1979 को अथवा इसके बाद किया जाएगा।

सिद्धान्त के रूप में, संभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि अपरिवर्तनीय साख्तपत्र के अंतर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के बैंक प्रॉफ इण्डिया टोकियो को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय पर भ्रवा की जाएगी।

4. अन्तर्राष्ट्रीय संविदा का टेण्डर देना

जब अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की जाए तब अन्य नियमों के साथ निम्नलिखित नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति की जाएगी :

(1) विज्ञापन बेकर

औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदाओं में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जाएगी।

(2) बोलियों के मांगने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का अन्तराल

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा के महत्व और पेचीदगी के ऊपर निर्भर करेगा। सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिन स्वीकृत किए जाने चाहिए। किन्तु अनुमति समय प्रत्येक संविदा से संबंधित हालातों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(3) बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों को अन्तिम पावती के लिए और बोली खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान की बोली आमंत्रण में बोधित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

(4) बोली बाण्ड या गारंटियां

बोली करने के मामले में, बोली बांड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं, किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उपयुक्त बोलीकार निरमाहित हो जाए।

बोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

(5) मापदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह वर्णित जाना चाहिए कि आपान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

(6) बाण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिक्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण

निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें केवल बाण्ड नाम, सूची संख्या या विशेष धनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं और कम से कम उस विशिष्टिकरण के बराबर निष्पादन और गुण उनमें हैं।

(7) गारंटी और निष्पादन बाण्ड

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लिए जमपूरत जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिए। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है।

(8) निर्धारित क्षति

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्वगी में फालतू खर्च होता हो, राजस्व की हानि हो या आयातक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाक्यांश जोड़े जाने चाहिए।

(9) विषय स्थितियां (फोर्स मेज्योर)

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने बाधितों को न पूरा करना उस ह्रासत में एक बूक नष्टी माना जाएगा यदि ऐसी बूक विषय स्थितियों (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की जानी है)।

(10) झगड़ों का निपटारा

झगड़ों के निपटारा से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल द्वारा बनाए गए “समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों” या भारतीय एवं समुद्रपार के संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थाओं पर आधारित होने चाहिए।

(11) मूल्यांकन

अनुबन्ध-6

[संदर्भ खण्ड-5 कडिका-5 (2)]

गारंटी बांड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या

विनांक के आधार पर

द्वारा

(जिसे बाद में आयात कहा गया है)

के आयात के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें बाद में “सरकार” कहा गया है) के हेतु येन/यूएस डास्तर और पौण्ड स्टर्लिंग में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होने हुए हम आयातक बैंक की प्रार्थना पर उपर्युक्त अनुदान सहायता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निश्चित रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखों में जमा करके के लिए भुगतानों की सूचना पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर बैंक प्रॉफ इण्डिया, टोकियो द्वारा व्यय की गई धनराशि को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक मूचना संख्या 8 आई टी सी (पी एन)/76—, विनांक 17-1-76 में निहित अनुसार अथवा सार्वजनिक सूचनाएं/डी परिपत्र में समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार परिवर्तित मिश्रित दर के हिसाब से और इस धनराशि में समुद्रपार संभरक की भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अधिधि पर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जोड़ कर

और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15% वार्षिक दर से ब्याज को जोड़ कर धनराशि जमा करने की व्यवस्था करने का एवम् द्वारा बचन देने है। बैंक ऑफ इण्डिया, टांकियो से प्राप्त आयात प्रवेशों का परक्रम सेट आयातक को तभी लौटाया जाएगा जब कि उपर्युक्त अपेक्षित रूपरा जमा कर दिया गया हो।

2. हम दि... बैंक, समय-समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निविष्ट करे, आयातक द्वारा सरकार को वेध अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो... रूप से अधिक न हो या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा वेध या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को और समुद्र पार सभरक को भुगतान करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इससे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं अतिपूर्ति करने का और सरकार को अतिपूर्ति के वायित्व से मुक्त रखने का भी बचन देने हैं। उक्त भुगतान से आयातक द्वारा या उसकी तरफ से हमारे... बैंक द्वारा सरकार को वेध धनराशि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का त्रुटि सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे बैंक पर लागू होगा।

3. हम... बैंक, आगे हम बात पर सहमत है कि सविदा के अन्तर्गत आयाती के मूल्य में या जा माल छुड़ाना बाका है उसके मूल्य में उपयुक्त पैरा एक में उल्लिखित मुद्रा विनियम के विभिन्न दर में परिवर्तन होने की स्थिति में, जब में परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन के अनुशात में हम बैंक गारंटी बाड को धनराशि का समायोजित कर लिया जाएगा।

4. हम... बैंक, आगे सहमत है कि इसके अन्तर निहित यह गारंटी उक्त करार/सविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रूपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारंटी को हैमियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिए गए हो।

5. इस गारंटी पर आयातक या दि... बैंक, के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने में प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी का प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के सदर्भ में या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थान, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तिथों से सम्बन्धित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि... बैंक को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किंगों प्रकार का स्वतन्त्रता का पर्येण करने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि... बैंक, अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

6. हम... बैंक अन्त में यह बचन लेते है कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी बाबू अवधि के दौरान रह नहीं करेगे।

7. इस बाड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व... रूपए (ब्याज और कमीशन प्रसार जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबन्धित है और यह गारंटी दिनांक... तक और जब तक इस निधि से 6 महीनो के भीतर इस गारंटी के अन्तर्गत आये पूर्ण नहीं कर दिए जाते है और जब तक अगले 6 महीनो के भीतर उन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्यवाही नहीं की जाती, जब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात् दिनांक... तक इस बाड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकारों से छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगा।

दिनांक... 1979

हस्ताक्षर... बैंक

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनका आर से श्री

(नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

जिस निधि तक साक्ष-पत्र का वेध रखने की आवश्यकता होगी है उस तिथि में एक महीना जोड़कर यह निधि गिना जाएगा।

टिप्पणी—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जाती है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है।

अनुबन्ध-7

[खण्ड-7, कडिका-7 (5)]

बैंक गारंटी की रिटर्न के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय प्राधिकार्य विभाग

यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,

पानियामेट स्ट्रीट,

नई दिल्ली-110001

महोदय,

हम... रुपये के लिए बैंक गारंटी संख्या... दिनांक... के अन्तर्गत अपने दायित्व के अनुशात में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपये की विस्तृत सूचना नीचे इस आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और हमें लौटाई जाए—

1. जिसकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी उस आयातक/लाइसेंसधारी का नाम और पूरा पता

2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक, मूल्य उसके अधीन आयात के लिए अनुमेष किए गए उपकरण और/या पण्य वस्तुओं का वक्षिप्त विवरण।

3. वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है।

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) 2.9 बिलियन येन की जापान अनुदान सहायता

4. आयाती के ओर जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग से ब्यौरा दिया जाना है—

(क) येन/यू एस डॉलर/पीड में बीजक की धनराशि (कुल)

(ख) जमा किए गए रुपये की धनराशि

(ग) संबंधित चानान संख्या और दिनांक एच राजकोष/बैंक का नाम

(घ) यदि रुपए वर्णनी हुन्डी द्वारा जमा किए गए हों तो वर्णनी हुन्डी की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ वर्णनी हुन्डी बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली का भेजी थी उसकी संख्या और दिनांक।

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (येन/यू एस० स्टर्लिंग/पीड)

2 हम प्रमाणित करते हैं कि —

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए प्राधिकरण (एन) से उपलब्ध
यें की शेष धनराशि
उपयोग नहीं की गई/उपयोग नहीं का जाएगा।

(2) विषयाधीन बैंक गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व विधिवत
पूर्ण हो गया है।

3 हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो
का ब्याज और बैंक प्रभार हम सौदे से संबंधित समुदायार मभरको
के बैंकरो, के भाड़े बैंक आफ इंडिया, टोकियो को हमारे द्वारा
भेज दिए गए हैं।

4 अनुसंधान है कि बैंक गारंटी रिहा की जाए और निरस्त करने
के लिए हमें नोटा की जाए।

भारतीय,

[बैंक के लिए और बैंक की ओर से प्राधिकृत अधिकारी]

*जो भी लागू हो।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO 49-ITC(PN)/79

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th September, 1979

Subject: Terms and conditions governing the issuance of
import licences for public and Private sector imports
under the Japanese Grant Aid for 1978-79 extended
by the Government of Japan.

No. IPC/39/18/78.—The terms and conditions governing
the issuance of import licences for Public and Private Sector
imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion
(2,900,036,000) extended by the Government of Japan for
1978-79 as given in Appendices I and II respectively to this
Public Notice are notified for information.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller
of Imports and Exports

APPENDIX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC
NOTICE NO. 49-ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979
LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC
SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT
AID OF YEN 2.9 BILLION (2,900,036,000) FOR 1978-
79 EXTENDED BY THE GOVT. OF JAPAN
Section I—General Conditions:

I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion extended
by the Government of Japan is untied in favour of OECF
and developing countries. Accordingly the commodities and services,
incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be
imported from Japan and all countries enumerated in the list
at Annexure-I which will be the eligible source countries under
this Grant. However, if commodities imported under the
licence contain components originating from a non-eligible
source country or countries, it should be ensured by the
importer, while negotiating a supply contract, that the total
c.i.f. cost, including import duties, of such components imported
into the country of the supply contract is less than 30 per
cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case,
a certificate to this effect should be obtained from suppliers
and attached to the supply contract. The list of eligible commodities
that can be imported under this Grant Aid is at
Annexure-II.

I (ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.9
billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code
for the first and second suffix will be "S/JN". These will also
be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the
import licence.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted
against the import licence, except bank charges which may
be remitted through normal banking channels. Any payment

towards Indian Agent's commission should be made in Indian
rupees to the agents in India. Such payments however,
will form part of the licence value and will, therefore be
charged to the licence.

I (iv) The import licence will be issued on CIF basis with
an initial validity of 12 months. For extension of the validity
of the licence, the licensee should approach the licensing
authority concerned who shall consult the Department of
Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I (v) Firm order must be placed on C&F basis on the over-
seas suppliers located in Japan and in other eligible countries
mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary,
Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of
Finance, North Block, New Delhi (Within 4 months from the
date of issue of the import licence. "Firm Orders" mean,
purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas
supplier duly supported by order confirmation by the latter
or purchase contract duly signed by both the Indian importer
and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of overseas
suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents
are not acceptable.

I (vi) This condition of the placement of contracts within
4 months period will be treated as not having been complied
with unless complete contract documents reach the Ministry
of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section,
within four months from the date of issue of the import
licence. If firm orders as explained in para 1 (v) above cannot
be placed within 4 months for valid reasons, the licensee
should submit the import licence to the concerned licensing
authorities giving reasons why ordering could not be completed
within 4 months. Such requests for extension in the ordering
period will be considered on merit by the licensing authorities
who may grant extension upto a further maximum period of
4 months. If however, extension is sought beyond 4 months
from the date of issue of this import licence, such proposals
will invariably be referred by the licensing authorities to the
Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of
Finance, North Block, New Delhi who will consider such
extension on the merits of each case and communicate their
decision to the licensing authorities for communication to the
licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted
that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating
a supply contract

II (i) (a) The C&F value of the contract should be expressed
in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction
less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude
Indian Agent's commission, if any, which should be paid in
Indian rupees. In no circumstances the contract value should
be expressed in Indian rupee or in any other currency. The
FOB cost and freight amount may be shown separately but it
should be clarified in the contract whether the freight charges
will be payable on actual basis or whether the freight charges
indicated in the contract would be the amount payable
irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash
basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese
suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation
should be in English only.

II (ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million
or US \$ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of
Indian agents commission) the licensee is free to effect pur-
chases directly from the suppliers without recourse to inter-
national tender enquiries from the countries listed in
Annexure-I.

II (iii) Where, however the supply contracts exceeds the
value limit prescribed in II (ii) above (exclusive of Indian
Agents commission), the following procedure for procurement
should be rigidly followed:—

(a) Formal Open International Tendering

(b) Formal, elective International Tendering

(c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or Procurement, as the case may be from the eligible source countries

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct Purchases where

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries;
2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirements;
3. where purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of Para II(iii) above cannot be taken recourse to a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will give necessary approval on merits of each case.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to the following points should be borne in mind:—

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vii) Eligibility of Supplier

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 "and will be subject to the approval of the Government of India."

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents, as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where Suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below:—

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in _____ (eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source country, or juridical persons registered and incorporated in the eligible source countries."

III(vi) Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering a certificate to the following effect should be furnished:—

- (i) Name of the Newspaper(s) in which the bid specifications was published;
- (ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

NOTE:—For detailed procedure for procurement of commodities and finalisation of supply contract see Annexure

Section IV—Contract Approval by Government of India

IV(i) As soon as the orders are finalised, the Licensee should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the supplier supported by order confirmation in writing by the supplier or their photo copies complete in all respects to gether with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) TCM Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAAA and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo the importer, importer's Bank in India and TCM Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the C A A & A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier along with interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of

actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976 the exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad—purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grand Aid)

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

NOTE :—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned banks in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI.—Miscellaneous provisions

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure—F under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

VI(v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :—

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V—Detailed procedure for procurement.

ANNEXURE I

Ref : Section 1—Para 1(v)

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. OECD Countries

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland,
France,
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
Newzealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
The United Kingdom and the United States

B. Developing Countries & Territories

(b1) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I. AFRICA, North of Sahara

Egypt

Morocco

Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara

Angola

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep

Chad

Comoro Islands

Congo, People's Republic of Dahomey (1)

Equatorial Guinea

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Mozambique

Niger

Portuguese Guinea

Reunion

Rhodesia

Rwanda

St. Helena and dep (2)

Sao Tome and Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Swaziland

Togo, Afars and Issas

Togo

Uganda

Un. Rep. of Tanzania

Upper Volta

Zaire Republic

Zambia

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas

Barbadoses

Belize

Bermuda

Costa Rica

Cuba

Dominican Republic

El Salvador

Guadeloupe

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Martinique

Mexico

Netherlands Antilles

| | |
|---------------------------|---|
| Nicaragua | Hong Kong |
| Panama | Khmer Republic |
| St. Pierre & Miquelon | Korea Republic of Lacs |
| Trinidad and Tabago | Macuo |
| West Indies (Br.) n.l.e. | Malaysia |
| (a) Associated States (1) | Phillippines |
| (b) Dependencies (2) | Singapore |
| IV. AMERICA, South | Taiwan |
| Argentina | Thailand |
| Bollvia | Timer |
| Brazil | Vietnam, Rep. of Viet-Nam Dem. Rep. |
| Chile | (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Caristephe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent. |
| Colombia | (2) Main islands ; Montserrant, Gayman, Turks and Caicos and British Virgin Islands. |
| Falkland Islands | (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaitwain. |
| French Guiana | (4) Including Aden and various sultanates and emirates. |
| Guyana | (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands the Tuamotu-Gambler Group and the Marquesas Islands. |
| Paraguay | (6) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam). |
| Peru | VIII. OCEANIA |
| Surinam | Cock Islands |
| Uruguay | Fiji |
| V. ASIA, Middle East | Gilbert & Ellice Is. |
| Bahrain | French Pelynesia (5) |
| Israel | Nauru |
| Jordan | New Caledonia |
| Lebanon | New Hebrices (Br. and Fr.) |
| Oman | Hieu |
| Syrian Arab Republic | Pacific Islands (US) (6) |
| United Arah Emirates (3) | Papua New Guinea |
| Yemen Arab Republic | Solomon Islands (Br.) |
| Yemen, People's D.R. (4) | Tongo |
| VI. ASIA, South | Wallis and Futuna |
| Afghanistan | Western Samoa |
| Bangladesh | IX. EUROPE |
| Bhutan | Cyprus |
| Burma | Gibraltar |
| Maldivis | Greece |
| Nepal | Malta S |
| Pakistan | |
| Sri Lanka | |
| VII. ASIA, Far East | |
| Burnei | |

| | |
|------------|--|
| Spain | 9 Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project |
| Turkey | |
| Yugoslavia | 10 Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon |

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuador

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001

Subject —Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 29 billion for 1978-79.

Sir,

In connection with the import of . . . from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods

(f) Gross C&F value of contract (in Yen)

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

ANNEXURE II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1 Rolls

2 Steel including special steel & alloy steel

3 Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors

4 Chemicals

5 Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures

6 Components, attachments and spares for power tillers

7 Machinery, components attachments, spares and raw materials

8 Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India

- (j) Name and Address of the Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate)
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and Address of the Importer's bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No. date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE IV

No.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s _____ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents, if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto _____.

Yours faithfully,
Accounts Officer

Copy forwarded to: —

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importer's Banker _____ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the

Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1978-79—(Yen 2.9 billion Grant Aid).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer,

ANNEXURE V

Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

I. Introduction more

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this guide lines.

II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid :

- (1) Formal Open International Tendering.
- (2) Formal Selective International Tendering.
- (3) Informal International Competitive Procurement.
- (4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases.

- (i) Where the amount of a proposed contract does not exceed 300,000,000.—, US Dollar 1,500,000.—or Pound Sterling 800,000.—, in terms of currency of the contract.
- (ii) Where the number of qualified suppliers is limited.
- (iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standardization of equipment, or because of special design requirements.
- (iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

1. Conditions of Commodities

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the fol-

lowing formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above :

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Supplier's FOB Price

2. Conditions of Supplier :

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer :

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency :

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (C 1.00) or One Penny (d. 1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid :

- (1) Name and Nationality of Supplier and Importer
- (2) Number and Date of the Contract
- (3) Name and Origin of the Commodities
- (4) Contract Price and Quantity
- (5) Payment Terms
- (6) Delivery and Shipment Schedule
- (7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract :

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)."

6. Payment :

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17th March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

IV. International Tendering

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others :

1. Advertising :

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for

international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees :

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

5. Standards :

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

6. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds :

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages :

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the Inter-

national Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation :

APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE NO. 49 ITC (PN)/79 DATED 24-9-1979.

LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PRIVATE
SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID
OF YEN 2.9 BILLION FOR 1978-79 EXTENDED BY THE
GOVERNMENT OF JAPAN

Section I—General Conditions :

I(i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of CECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries, enumerated in the list at Annexure I which will be the eligible source countries under this Grant. However, if commodities imported under the licence contain components originating from a non-eligible source country or countries, it should be ensured by the importer, while negotiating a supply contract, that the total c.i.f. cost, including import duties, of such components imported into the country of the supply contract is less than 30 per cent of the f.o.b. value of the supply contract. In such a case, a certificate to this effect should be obtained from suppliers and attached to the supply contract. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.9 billion Japanese Grant Aid for 1978-79". The licence code for the first and second suffix will be "S/IN". These will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licencee.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (TCM Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (TCM Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 30-6-1981.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i) (a) The value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Panny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) For individual imports not exceeding Yen 300 million or US \$ 1,500,000 or £ 800,000 in value (exclusive of Indian agents commission) the licensee is free to effect purchases directly from the suppliers without recourse to international tender enquiries from the countries listed in Annexure-I.

II(iii) Where, however, the supply contracts exceed the limit prescribed in II (ii) above in value (exclusive of Indian agents commission), any one of the following procedures for procurement should be rigidly followed :

- (a) Formal Open International Tendering
- (b) Formal selective International Tendering
- (c) Informal International Competitive Procurement

II(iv) Any reference to International Tendering or International Procurement will mean tendering or procurement, as the case may be, from the eligible source countries.

The above procedure may be relaxed in favour of Informal Competitive procurement or Direct purchase where—

1. a number of qualified suppliers exist in one particular country or in a limited number of countries.
2. purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the interchangeability or standardisation of equipment or because of special design requirement.
3. Purchases are in the category of emergency procurement.

The licensee is therefore advised that in case where the procedure at (a) and (b) of para II (iii) above cannot be taken recourse to, a reference to the Department of Economic Affairs shall have to be made who will consider each such case on merits.

II(v) Where Formal Open International Tendering is resorted to, the following points should be borne in mind :—

- (a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.
- (b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.
- (c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(vi) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(vii) Eligibility of Supplier

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person governed substantially by nationals of the eligible countries.

Section III: The following provision should be specifically incorporated in the supply contract:—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 17th March, 1979 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.9 billion for 1978-79 and will be subject to the approval of the Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through in "Authorisation to pay" (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978-79.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

III(v) A certificate in the form indicated below:—

"I (We) hereby state that my (our) Company has been registered in.....(eligible source country) and is governed by nationals of the eligible source countries or juridical persons registered and incorporated in the eligible source Countries".

Section—IV Detailed Procedure for procurement and finalisation of supply contract has been indicated in Annexure-V

Section—V Contract Approval by Government of India

V(i) Within the stipulated period for placement of firm orders, the licensee should forward to the Under Secretary, (TCM Section), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies, complete in all respects, together with two photo-copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure—VI duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

Where supply contract is based on formal Open International Tendering or Formal Selective International Tendering, a certificate to the following effect should be furnished in duplicate:—

- (i) Name of the Newspapers in which the bid specification was published;
- (ii) Name of parties who quoted against the tender enquiry;
- (iii) the reason for selecting a particular offer indicating whether it is the lowest technically suitable bid.

V(ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed.

The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure—VI. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)/74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E.

This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licensee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section VII below.

V(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, TCM Section will approve the contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, 1st Floor Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

Section VI—Payment to the Overseas Suppliers—A/P.

(i) On receipt of the documents mentioned in Section V (iii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and T.C.M. Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

VI(ii) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA & A.

VI(iii) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

VI(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section VII—Responsibility for rupee deposit :

VII(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure—III who should release these negotiable sets of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public

Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1978-79. —(Yen 2.9 billion Grant Aid)

VII(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VII(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importers' Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VII(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

VII(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for this purpose be made in the form laid down in Annexure—VII.

Section—VIII Miscellaneous provisions

VIII(i) Reports on the utilisation of the import licence

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VIII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VIII(iii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VIII(iv) Future Instructions

The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1978-79 from Japan.

VIII(v) Breach or violation

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VIII(vi) List of Annexures :

Annexure I : List of eligible source countries

Annexure II : List of eligible commodities

Annexure III : Form of request for issue of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure IV : Form of letters of Authorisation to Pay (A/P)

Annexure V : Detailed procedure for procurement

Annexure VI : Form of Guarantee Bond

Annexure VII : Form of Application for release of Bank Guarantee.

ANNEXURE—I

[Ref. Section I—Para I(v)]

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A OECD Countries

Australia

Austria

Belgium

Canada

Denmark

Finland

France

The Federal Republic of Germany

Greece

Iceland

Ireland

Italy

Japan

Luxembourg

The Netherlands

New Zealand

Norway

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

The United Kingdom and
The United States.

B Developing Countries & Territories

(b) Non-O.P.E.C. Developing Countries

I. Africa North of Sahara

Egypt

Morocco

Tunisia

II. Africa, South of Sahara

Angola

Botswana

Burundi

Cameroon

Cape Verde Islands

Central African Rep.

Chad

Comoro Islands

Congo, People's Republic of Dahomey (1)

Equatorial Guinea

Ethiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Ivory Coast

Kenya

Lesotho

Liberia

Malagasy Republic

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Malawi | El Salvador |
| Mali | Guadeloupe |
| Mauritania | Guatemala |
| Mauritius | Haiti |
| Mozambique | Honduras |
| Niger | Jamaica |
| Portuguese Guinea | Martinique |
| Reunion | Mexico |
| Rhodesia | Netherlands Antilles |
| Rwanda | Nicaragua |
| St. Helena and Dep (2) | Panama |
| Sao Tome and Principe | St. Pierre & Miquelon |
| Senegal | Trinidad and Tobago |
| Seychelles | West Indies (Br.) n.i.e. |
| Sierra Leone | (a) Associated States (1) |
| Somalia | (b) Dependencies (2) |
| Sudan | |
| Swaziland | IV. America, South |
| Terr. Afars and Issas | Argentina |
| Togo | Bolivia |
| Uganda | Brazil |
| Un. Rep. of Tanzania | Chile |
| Upper Volta | Colombia |
| Zaire Republic | Falkland Islands |
| Zambia | French Guiana |
| | Guyana |
| | Paraguay |
| | Peru |
| III. America, North and Cent. | Surinam |
| Bahamas | Uruguay |
| Barbados | |
| Belize | V. Asia, Middle East |
| Bermuda | Bahrain |
| Costa Rica | Israel |
| Cuba | Jordan |
| Dominican Republic | Lebanon |
| | Oman |
| | Syrian Arab Republic |
| | United Arab Emirates (3) |

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da
Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacius,
St. Martin (Southern Part).

Yemen Arab Republic

Yemen, People's D.R. (4)

VI. Asia, South

Afghanistan

Bangladesh

Bhutan

Burma

Maldivis

Nepal

Pakistan

Sri Lanka

VII. Asia, Far East

Borneo

Hong Kong

Khmer Republic

Korea, Republic of

Laos

Macao

Malaysia

Philippines

Singapore

Taiwan

Thailand

Timor

Vietnam, Rep. of

Viet-Nam Dem. Rep.

VII. OCEANIA

Cook Islands

Fiji

Gilbert & Ellice Is.

French Polynesia (5)

Nauru

New Caledonia

New Hebrides (Br. and Fr.)

Hieu

Pacific Islands (US) (6)

Papua New Guinea

Solomon Islands (Br.)

Tongo

Wallis and Futuna

Western Samoa

IX. EUROPE

Cyprus

Gibraltar

Greece

Malta S

Spain

Turkey

Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC

Algeria

Bolivia

Libyan Arab Republic

Gabon

Nigeria

Ecuador

Venezuela

Iran

Iraq

Kuwait

Qatar

Saudi Arabia

Abu Dhabi

Indonesia

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands; Caroline Islands, Marshal Islands and Marine Islands (except Guam).

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

ANNEXURE—II

ELIGIBLE COMMODITY LIST

1. Rolls
2. Steel including special steel and alloy steel
3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors
4. Chemicals
5. Spares, components and raw materials for Indo-Japanese Joint Ventures
6. Components, attachments and spares for power tillers
7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials
8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India
9. Machinery and equipment for the Bombay High Offshore Development Project
10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.

ANNEXURE—III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION
TO PAY"

No

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Imports from Japan under the Japanese Grant Aid
of 2.9 billion for 1978-79

Sir,

In connection with the import from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and address of the Indian importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross C&F value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agency commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net C&F Value (in Yen) for which the A/P is required.

(i) Name and date of the contract with Suppliers.

(j) Name and Address of the Supplier and attach an eligible certificate (in duplicate).

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transshipment/part-shipment permitted or not permitted).

(o) Name and Address of the Importer's bank in India.

(p) Number, date and value of the Bank Guarantee (s) indicating the period(s) upto which the same is (are) valid.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

Yours faithfully,

ANNEXURE—IV

No.

Government of India
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are

hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix).

2. Please advise the Contractor of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy each of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents if any, payable to you by the importer will also be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto _____

Yours faithfully,

Accounts Officer

Accounts Officer

ANNEXURE—V

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

2. Importer's Banker _____ They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76, dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances -843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan for 1978-79/(Yen 2.9 billion Grant Aid).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TCM) Ministry of Finance Department of Economic Affairs, New Delhi.

Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese Grant Aid

I. Introduction

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion extended by the Government of Japan shall be used with due attention to efficiency and non-discrimination among the eligible source countries for procurement of commodities and services incidental thereto in accordance with the procurement procedures set out in this Guidelines.

II. Selection of Procurement Procedure

The following procedures shall be applicable to the procurement of Listed Commodities under the Grant Aid :—

- (1) Formal Open International Tendering
- (2) Formal Selective International Tendering
- (3) Informal International Competitive Procurement
- (4) Direct Purchases.

(a) In the case of the procurement by the government and/or a government agency, Formal Open International tendering or Formal Selective International Tendering shall be applied.

(b) In case of non-government procurement, any of the procedures mentioned above may be applied.

(c) It is, however, possible under this Grant Aid to accept the procurement through Informal International Competitive Procurement or Direct Purchases in the following cases :—

- (i) Where the amount of a proposed contract does not exceed y 300,000,000.—, US \$ 1,500,000.—or Pound Sterling 800,000.—in terms of currency of the contract
- (ii) Where the number of qualified suppliers is limited.

(iii) Where purchase of a commodity by reference to a particular specification, trade name or designation is necessary in order to assure the inter-changeability or standardization of equipment or because of special design requirements.

(iv) Where either procedure (1) or procedure (2) by the reason other than the case (i), (ii) and (iii) above (e.g. in case of emergency procurement) is inapplicable.

(d) In any case mentioned above, Importer shall get a confirmation of the Borrower concerning the eligibility of procurement in accordance with the procurement procedure set forth in this Section 1-3.

III. Conditions of Contract

Any contract to be financed under this Grant Aid shall fulfill the following conditions.

1. Conditions of Commodities :

As the use of this Grant Aid is limited to financing expenditures for Listed Commodities produced in the eligible source countries, the subject items of the Contract shall be Listed Commodities produced in the eligible source countries and to be shipped to an Indian port from the eligible source countries. If the imported portion from non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) of the following formula, Listed Commodities will be financed even if the imported portion from non-eligible source countries is included as a part of the Listed Commodities in the items of the Contract Formula mentioned above :

$$\frac{\text{Imported Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

2. Conditions of Supplier :

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered in the eligible source countries.

3. Conditions of Importer :

The procurement of any Commodities by the armed forces or their affiliated organizations of India shall not be eligible under the Loan.

4. Denomination of Currency :

The Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen, United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction less than one Yen (Y 1.00), One cent (c 1.00) or One Penny (d. 1.00) respectively.

5. Standard Form of Contract :

(a) The following items shall be inserted in the Contract to be financed under this Grant Aid :—

- (1) Name and Nationality of Supplier and Importer
- (2) Number and Date of the Contract
- (3) Name and Origin of the Commodities

(4) Contract Price and Quantity

(5) Payment Terms

(6) Delivery and Shipment Schedule

(7) Other General Regulations

(b) The Contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian Importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies, are also acceptable.

(c) The following statement of eligibility by the Supplier shall be added to each contract :—

"I (We) hereby state that my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)."

6. Payment :

Each payment shall be made on and after the date of signing of the Grant Aid i.e. 17 March, 1979.

In principle, the full amount of a shipment shall be paid to the supplier on cash basis at each time of presentation of the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo.

IV. International Tendering :

When International Tendering is applied, the procurement shall be made in accordance with the following principles, among others.

1. Advertising :

On all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

2. Time Interval Between Invitation and Submission of Bids :

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

3. Bid Opening Procedures :

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

4. Bid Bonds or Guarantees :

In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement, but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

5. Standards :

If national standards with which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

6. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features.

In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

7. Guarantees and Performance Bonds :

Bidding documents may require some form of surety for guarantees, if necessary. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond.

8. Liquidated Damages :

Liquidated damages clauses, if necessary, should be included in bidding documents when delays in delivery will result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other benefits to the Importer.

9. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

10. Settlement of Disputes :

Provisions dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas Supplier.

11. Evaluation

[Ref. Section V—Para V(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens/US Dollars and £ Sterling for the import of _____ by _____ (hereinafter called the 'importer') against the import licence No. _____ dated _____ issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we _____ Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices/A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo, will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the _____ (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. _____, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us _____ (Bank), shall be final and binding on us _____ (Bank).

3. We, _____ (Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, _____ (Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to the enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the _____ (Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the _____ (Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the _____ (Bank) from its such liability.

6. We _____ (Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with provision consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. _____ (plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of _____ (month) 19_____. Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto _____ all Government's rights under this bond/guarantee shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the _____ day of _____ 19

for _____ (Bank)

Accepted for and on behalf of the

President of India by Shri _____

(Name and Designation)

Signature

Signature

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

Note : The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE—VII

[Section VII-Para VII (v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,

Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs,

UCO Bank Building, 1st Floor,

Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in the discharge of our obligations under Bank Guarantee No. _____ dated _____ for an amount of Rs. _____ with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licencee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence No., date, value, brief description of the equipment and/or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation (s) obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each authorisation).

(a) Letter No and date.

(b) Amount of Authorisation.

(c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation).

(a) Amount of Invo. (net) in Yen /US \$/ £.

(b) Amount of Rupee deposit.

(c) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(d) If by demand draft, No. and date of the demand draft No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance utilised (Yen/US \$/£) in each Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen _____ available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

*Whichever is applicable.

(2) Our obligation under the Bank Guarantee in question have been fully discharged.

IV. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

Yours faithfully,
Authorised Agent for and on
behalf of the Bank.